THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASING (SHRI AJIT PANJA': (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Surplus of Milk and Mlik Products

1402; SHRl RAM AWADHESH SINGH; Will the Minister of AGRI-CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a If act that as a result of Operation Flood I, II and III, there is surplus of mlik and milk products in states like Maharashtra and Gujarat;

(b) whether milk products are likely to be exported especially to cater to affluent Indians living abroad; and

(c) whether as a result of gifts under Operation Flood-Ill, there is a likelihood of surp1us of milk products in the country and subsequent reduction in prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRl YOGENDRA MAKWANA): (a) As a result °f Operation Flood programmes and implementation of various programmes at Central and State levels, milk production in Maharashtra and Gujarat has increased. This does not, however,
imply a real surplus of milk. There could be seasonal surplus in a certain year in a given State following a good agricultural year which might decline under the impact of a subsequent drought. Thus the concept of surplus is really contextual.

(b) There is no such proposal under consideration.

(c) No, Sir. The conserved gift com modities under Operation Flood Hi are to serve the twin objectives of generating funds for the programme and provide for a buffer stock necessary take care of lean years. The commodities will be priced in such a way as not to affect domestic prices or production.

डी०सी०एम० और डी०डी०ए० द्वारा धोखाधड़ी

1403. श्री अरवनो कुमार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कुछ समय पहले दिए गए आश्वासनों के अनुसार, डी० सी० एम० और डी० डी० ए० द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी ; यदि हां, तो क्या समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है ; यदि हां, तो समिति का प्रतिवेदन कब तक सभा पटल पर रख दिए जाने की संभावना है; और

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपर्युक्त जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर या श्रम विभाग द्वारा डी० सी० एम० को बन्द करने की अनुमति देने से इनकार करने के आधार पर 1 फरवरी, 1983 का प्रस्ताव संख्या 26 और 1 अगस्त, 1986 का प्रस्ताव संख्या 3 वापस ले लिए गए हैं ; और यदि हां, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्य सभा में दिनांक 2-5-85 को श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सामान्य रूप से विशेषरूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन और सरकार के विरूद्ध आलोचना तथा आरोपों को गम्भीरता से लेते हुए डी० सी० एम० परिसर के पुनर्विकास को अनुमति देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण के 1-2-83 के संकल्प संख्या 26 को पारित करने, नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कम्पनी की भूमि के सम्बन्ध में कम्पनी को छूट देने और मिल को बन्द करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमति देने से इन्कार करने की जांच पड़ताल